THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) According to the Delhi State AIDS Control Society, there is no case of donation of blood by professional donors in various Government hospitals in the capital. This has been confirmed by surveys carried out by Drugs Control Department, Government, of NCT of Delhi from time to time.

(b) Does not arise.

(c) No case of supply of date expired blood has come to the notice of Drugs Control Department of Govt. of NCT of Delhi.

(b) Does not arise.

सरकारी अस्पतालों पर दबाव कम करने के उपाय

*363. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों पर दबाव को कम करने हेतु कुछ उपाए किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की जाएगी;

(घ) क्या सरकारी अस्पतालों को सुदृढ़ बनाने और उनके कार्यकरण में सुधार लाने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई): (क) से (ङ) सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में स्थापित अस्पतालों की संख्या 2694 (1951) से बढ़कर 13692 (1993), औषधालयों की संख्या 5306 (1951) से बढ़कर 28321 (1993) और पलंगों की संख्या 117179 (1951) से बढ़कर 843650 (1993) हो गई है। यह वृद्धि जनसंख्या में हुई वृद्धि की रफ्तार के अनुसार नहीं हुई है जिस से सरकारी अस्पतालों जो समाज के निम्न कम दौलतमंद वर्गों की जरूरतों की पूरा करते हैं, में अत्यधिक भीड़ हो गई है।

"स्वास्थ्य" राज्य का एक विषय है और राज्यों में लोगों की महसूस की गई जरूरतों को देखते हुए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना और स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त निवेश करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

सरकारी अस्पतालों में अत्यधिक भीड़ रेफरल पद्धतियों के अभाव के कारण भी है जहां रोगियों की जांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप जिला और जिला स्तर के अस्पतालों में की जा सकती है। प्रमुख सरकारी अस्पतालों पर दबाव को कम करने के लिए आन्ध्र प्रदेश (परियोजना व्यय 608.00 करोड़ रुपये), कर्नाटक (परियोजना परिव्यय — 546.00 करोड़ रुपये), पंजाब (परियोजना परिव्यय — 425.00 करोड़ रुपये), पश्चिम बंगाल, (परियोजना परिव्यय —689.00 करोड़ रुपये), उड़ीसा (परियोजना परिव्यय — 415.57 करोड़ रुपये) और महाराष्ट्र (परियोजना परिव्यय — 158.1 मिलियन अमरीकी डालर) द्वारा विश्व बैंक सहायता से उप जिला स्तर के अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोगियों की उपयुक्त जांच हो और सरकारी अस्पतालों में अत्यधिक भीड़ न होने देने के लिए स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे के विभिन्न स्तरों पर सुविधाएं प्रदान की जाएं, इस परियोजना के बाद के चरणों में और अधिक राज्यों को कवर करने का विचार है।

केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के लिए 1999-2000 के लिए योजना आवंटन इस प्रकार है:—

सफदरजंग अस्पताल	25.93 करोड़ रुपये
डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल	12.57 करोड़ रुपये
लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज	8.45 करोड़ रुपये
कलावती सरन बाल अस्पताल	5.82 करोड़ रुपये
जवाहरलाल आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी	13.50 करोड़ रुपये
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	81.00 करोड़ रुपये
स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	47.00 करोड़ रुपये

विभिन्न केन्द्रीय अस्पतालों में हाल में निम्नलिखित सुविधाएं विकसित की गई हैं:—

(i) केन्द्रीय विकलांग संस्थान, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में एक आर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स इन्जरी क्लिनिक की स्थापना की गई है।

(ii) सफदरजंग अस्पताल के हृद-वक्ष वाहिका शल्य चिकित्सा विभाग और हृद विज्ञान विभाग को 529 करोड़

रुपये की लागत से सुदृढ़ करने वाला प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है।

(iii) 16.44 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सफदरजंग अस्पताल में बहिरंग रोगी विभाग चरण-III का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है।

(iv) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 7.94 करोड़ रुपये की लागत से हृद-वक्ष वाहिका शल्य चिकित्सा विभाग की स्थापना संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित ले गया है। डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इस विभाग में 41 पद सृजित किए गए हैं।

(v) केन्द्रीय सरकार के तीन अस्पतालों नामतः सफदरजंग अस्पताल, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और संबद्ध अस्पतालों में आपात तथा दुर्घटना विभाग की सुविधाओं में 629.00 लाख रु० की लागत से चरणबद्ध ढंग से सुधार करने का निर्णय लिया गया है।

(vi) 115.86 लाख रुपये की धनराशि उपस्कर क्रय हेतु मंजूर हो गई है और सफदरजंग अस्पताल के वर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी विभाग को स्थितियों में सुधार करने की दृष्टि से विभिन्न सिविल और वैद्युत कार्य सम्पन्न करने के लिए 1996-97 के दौरान लगभग 100.00 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा 130 पद भी सृजित किए गए हैं।

(vii) डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल को लगभग 1980 वर्ग गज रकबे का एक त्रिकोना भूखंड आबंटित किया गया है जिससे कि उसके आपात और दुर्घटना विभाग की सेवाओं में बढ़ोत्तरी हो सके।

(viii) कलावती सरन बाल चिकित्सा अस्पताल में जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण सहायता के अंतर्गत 150 और अधिक पलंग बढ़ाए जा रहे हैं।

(ix) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ में लगभग 2 लाख वर्गफुट क्षेत्र में फैले हुए नैदानिक और अन्य सेवाओं के लिए ओ०पी०डी० खंड के निर्माण की पूरे होने के संभावना है। हृद और नेत्र रोग के उन्नत केन्द्रों से संबंधित कार्य को 9वीं योजनावधि के दौरान आरम्भ किए जाने का विचार है।

(x) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बहिरंग रोगी विभाग के कार्यकरण में सुधार लाने और जांच-पड़ताल/बहिरंग रोगी विभाग निदानालयों को कार्यशील बनाकर बहिरंग रोगी विभाग में भीड़-भाड़ कम करने का प्रस्ताव है।

(xi) पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान शिलांग में हृद विज्ञान और जठरांत्र रोग विज्ञान की अतिविशिष्टता में उपचार हेतु सुविधा वाले बहिरंग रोगी विभाग निदानालय आरम्भ हो गए हैं।

(xii) बहिरंग रोगी विभाग का कार्यसमय बढ़ाने और उपरान्ह में विशिष्टता वाले निदानालयों को संचालित करने की व्यवस्था कायम की जा रही है। जिससे प्रातःकालीन होने वाली भीड़ में कमी लाकर स्थान और उपलब्ध जनशक्ति का बेहतर उपयोग किया जा सके।

Achievements of Population Programme

*364. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what are the achievements of Government in respect of population programme;

(b) whether Government achieved their target of population control through implementation of the programme;

(c) what are the major reasons for the hindrance in the population programme and in which States the programme has not been implemented; and

(d) the major reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) and (b) Objective of Family Welfare programme has been to stabilise population of the country. The achievements in controlling growth of population have been substantial; (a) the birth rate in the country has declined from 41.7 in 1951—61 to 27.2 in 1997 as per Sample Registration System estimates, (b) the number of children per woman has come down from 6 in 1951 to 3.5 in 1995, (c) Contraceptive acceptance rate has reached 45.4 by March, 1998 and (d) Infact Mortality Rate has declined from 146 in 1951 to 71 in 1997. The goal of population stablisation however has not yet been achieved.

(c) and (d) The family planning programme has been under implementation in all the States.